ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण : एक कठिन चुनौती

Empowering Women Through Education: A Tough Challenge

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 21/11/2021, Date of Publication:23/11/2021

प्रदीप कुमार एक्का
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर, सरगुजा,
भारत

सारांश

भारत को विविधता की भूमि होने पर गर्व है। इसमें विभिन्न जातियों, समुदायों, भाषाओं, धर्मों, संस्कृति और लिंग के लोगों को शामिल किया गया है। यद्यपि लोग राजनीतिक स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, अधिकांश लोग निरक्षर हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। ऐसे विविध समुदायों के उत्थान और प्रगति के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक शिक्षा है।

2011 की जनगणना के अनुसार, सात वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है, साक्षर कहलाता है।ष् इस मानदंड के अनुसार, 2011 के सर्वेक्षण में राष्ट्रीय साक्षरता दर लगभग 74.07ः है। 2001 के सरकारी आंकड़े यह भी मानते हैं कि साक्षरता में वृद्धि की दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। इस वर्ष महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत 65ः थी जबकि पुरुष साक्षरता 82ः थी। भारतीय राज्यों के भीतर, केरल ने उच्चतम साक्षरता दर 93ः दिखाई है जबकि बिहार में औसत 63 8ः साक्षरता है। 2001 के आंकड़ों ने यह भी संकेत दिया कि देश में श्पूर्ण अशिक्षितों की कुल संख्या 304 मिलियन थी।

India is proud to be a land of diversity. It includes people of different castes, communities, languages, religions, cultures and genders. Although the people enjoy political freedom, most of the people are illiterate and live below the poverty line. One of the most powerful tools for the upliftment and progress of such diverse communities is education.

According to the 2011 census, every person above the age of seven who can read and write in any language is called literate. The 2001 government figures also assume that the rate of increase in literacy is higher in rural areas than in urban areas. This year female literacy was 65% of the national average while male literacy was 82%. Within the Indian states, Kerala has shown the highest literacy rate of 93% while Bihar has an average of 63% literacy. The 2001 figures also indicated that the total number of illiterate people in the country was 304 million.

मुख्य शब्द: महिलाओं का सशक्तिकरण, उच्च शिक्षा, महिलाओं की साक्षरता।
Keywords: Empowerment of women, Higher education, Literacy of women.

प्रस्तावना

विश्व बैंक के आंकड़ों में पाया गया कि भारत में 40 प्रतिशत से भी कम किशोर माध्यमिक विद्यालयों में जाते हैं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि 10-वर्षीय ग्रामीण बच्चों में से आधे बुनियादी स्तर पर नहीं पढ़ सकते थे, 60ः से अधिक करने में असमर्थ थे, और आधे 14 साल की उम्र तक पढ़ाई छोड़ देते थे।

भारत में उच्च शिक्षा की रिपोर्ट के अनुसार, विस्तार, समावेश, गुणवत्ता और वित्त से संबंधित मुद्दे, सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में मापी गई उच्च शिक्षा तक पहुंच 1950/51 में 0.7ः से बढ़कर 1960-61 में 1.4ः हो गई। 2006/7तक जीईआर बढ़कर लगभग 11 प्रतिशत हो गया। 2012 तक (11वीं योजना के अंत का उद्देश्य) इसे बढ़ाकर 15ः करना है। आइए दिए गए आंकड़ों पर एक विहंगम दृष्टि डालें -

Sn.	Particulars	India		Chhattisgarh	
		2001	2011	2001	2011
1.	Total Population	1028737436	1210193422	20833803	25540196
2.	Male Population	532223093	623724248	10474218	12827915
3.	Female Population	496514346	586469174	10359585	12712281
4.	Area in Sq. KM	3287240	3287240	135191	135191
5.	Density	325	382	154	189
6.	Sex Ratio	933	940	989	991
7.	Literacy Rate	64.8	74.04	65.18	71.04
8.	Male Literacy Rate	75.3	82.14	77.86	81.45
9.	Female Literacy Rate	53.7	65.46	52.40	60.59

Scanned by CamScanner

स्रोत

जनगणना, 2001, स्लम इंडिया जनसंख्या, 2001, छत्तीसगढ़ अध्ययन, 2002- आईएसआई, दिल्ली और एक्सआईडीएएस, जबलपुर, मुख्य चिकित्सा कार्यालय, रायपुर, 2005, इंटरनेट - छत्तीसगढ़ ऑनलाइन.इन - 2011, अंतरिम अनंतिम डेटा, 2011।

पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है। बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला होता है और उनमें से कई स्कूल छोड़ देती हैं। अमेरिकी वाणिज्य विभाग की 1998 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महिला शिक्षा के लिए मुख्य बाधा अपर्याप्त स्कूल सुविधाएं (जैसे स्वच्छता सुविधाएं), महिला शिक्षकों की कमी और पाठ्यक्रम में लिंग पूर्वाग्रह (अधिकांश महिला पात्रों को कमजोर और मजबूर)। भारत की महिला आबादी में साक्षर महिलाओं की संख्या ब्रिटिश राज के बाद से 1947 में भारत गणराज्य के गठन तक 2-6ः के बीच थी। सम्मिलित प्रयासों से 1961 में 15.3ः से 1981 में 28.5ः तक सुधार हुआ। 2001 में महिलाओं की साक्षरता कुल महिला आबादी के 50ः से अधिक थी, हालांकि ये आंकड़े विश्व मानकों और यहां तक कि भारत में पुरुष साक्षरता की तुलना में अभी भी बहुत कम थे। हाल ही में भारत सरकार ने महिला साक्षरता के लिए साक्षर भारत मिशन शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य महिला निरक्षरता को उसके वर्तमान स्तर से आधे से कम करना है।

1947 के बाद से भारत सरकार ने मध्याह्न भोजन, मुफ्त किताबें और वर्दी के कार्यक्रमों के माध्यम से लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रयास किया है। इस कल्याणकारी जोर ने 1951 और 1981 के बीच प्राथमिक नामांकन को बढ़ाया। 1986 में शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने प्रत्येक राज्य के सामाजिक ढांचे के अनुरूप और बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ शिक्षा का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इसने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए केंद्रीय है। नई नीति का उद्देश्य संशोधित ग्रंथों, पाठ्यचर्या, स्कूलों के लिए धन में वृद्धि, स्कूलों की संख्या में विस्तार, और नीति में सुधार के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन करना है। लड़कियों के व्यावसायिक केंद्रों और प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया; माध्यमिक और उच्च शिक्षा; और ग्रामीण और शहरी संस्थान। रिपोर्ट ने स्कूल में कम उपस्थिति जैसी समस्याओं को गरीबी से जोड़ने की कोशिश की, और घर के काम और भाई-बहन की देखभाल के लिए लड़कियों पर निर्भरता को दर्ज किया।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने गांवों में महिला शिक्षकों के माध्यम से भी काम किया है। हालांकि लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र अब अठारह है, लेकिन कईयों की शादी बहुत पहले ही हो जाती है। इसलिए, माध्यमिक स्तर पर, महिला ड्रॉपआउट दर अधिक है। भारत में महिलाओं की शिक्षा देश में जीवन स्तर को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक उच्च शिक्षित महिला साक्षरता दर बच्चों, विशेष रूप से महिला बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने और शिशु मृत्यु दर को कम करके, घर और घर के बाहर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि महिला साक्षरता दर के निम्न स्तर के परिणामस्वरूप उच्च स्तर की प्रजनन क्षमता और शिशु मृत्यु दर, खराब पोषण, कम कमाई की क्षमता और घर के भीतर निर्णय लेने की क्षमता की कमी होती है। महिलाओं का निम्न शैक्षिक स्तर भी बच्चों के स्वास्थ्य और रहने की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। भारत में किए गए एक सर्वेक्षण ने परिणाम दिखाए जो इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि शिशु मृत्यु दर महिला साक्षरता दर और शैक्षिक स्तर से विपरीत रूप से संबंधित थी। सर्वेक्षण शिक्षा और आर्थिक विकास के बीच संबंध का भी सुझाव देता है।

भारत में, यह पाया गया कि विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता दर के बीच एक बड़ी असमानता है। उदाहरण के लिए, जबकि केरल में वास्तव में महिला साक्षरता दर लगभग 86 प्रतिशत है, बिहार और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर लगभग 55-60 प्रतिशत है। इन मूल्यों को भारतीयों के स्वास्थ्य स्तर के साथ और अधिक सहसंबद्ध किया गया है, जहां यह पाया गया कि केरल सबसे कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश भारत में सबसे कम जीवन प्रत्याशा वाले राज्य हैं। इसके अलावा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर की असमानता भी भारत में महत्वपूर्ण है। भारत के 24 राज्यों में से 6 में महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम है। ग्रामीण राज्य राजस्थान में महिला साक्षरता दर 12 प्रतिशत से कम है।

कम साक्षरता दर के कारण

भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक अनुचित सुविधाओं और अकुशल शिक्षण स्टाफ जैसे पर्याप्त स्कूल बुनियादी ढांचे की अनुपस्थिति है। 2006-2007 में सभी छात्रों को समायोजित करने के लिए 6 लाख कक्षाओं की कमी है। इसके अलावा अधिकांश विद्यालयों में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। मध्य और उत्तरी भारत में सरकारी संचालित 188 प्राथमिक स्कूलों के अध्ययन से पता चला कि 59 प्रतिशत स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं थी और 89 प्रतिशत में शौचालय नहीं थे।

बेसिक शिक्षा पर एक सार्वजनिक रिपोर्ट (च्त्व्ठम्) टीम ने सर्वेक्षण किया और बताया कि भारत में 1999 में बहुत खराब बुनियादी ढांचा था और 2005 में किसी विशेष दिन शिक्षकों के स्कूलों से अनुपस्थित रहने की दर 25ः थी। 600,000 गांवों और शहरी झुग्गी बस्तियों में वृद्धि, श् मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षाश्, बमुश्किल योग्य श्पैरा शिक्षकोंश् द्वारा दिया जाने वाला बुनियादी साक्षरता निर्देश है। अखिल भारतीय में औसत छात्र शिक्षक अनुपात 1ध्42 है, जिसका अर्थ है शिक्षकों की कमी। इस तरह की अपर्याप्तता के परिणामस्वरूप एक गैर-मानकीकृत स्कूल प्रणाली बन गई जहां साक्षरता दर भिन्न हो

Scanned by CamScanner

सकती है। इसके अलावा, शिक्षा के लिए आवंटित व्यय 1951-2002 से सकल घरेलू उत्पाद के 4.3ः से अधिक नहीं था, जबकि कोठारी आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6ः था। यह भारत में साक्षरता की समस्या को और जटिल करता है।

गंभीर जातिगत असमानताएं भी मौजूद हैं। निचली जातियों के भेदभाव के परिणामस्वरूप उच्च ड्रॉपआउट दर और कम नामांकन दर हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने भारत में प्राथमिक विद्यालयों को पूरा करने वाले बच्चों के प्रतिशत पर क्रमशः 36.8ः और 37.7ः की सूचना एकत्र की। 21 फरवरी, 2005 को, भारत के प्रधान मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर दुख हुआ कि कक्षा में नामांकित 100 में से केवल 47 बच्चे ही कक्षा आठ तक पहुँचते हैं, जिससे स्कूल छोड़ने की दर 52.79ः है।ष् यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 35 मिलियन, और संभवतरू 60 मिलियन, 6-14 वर्ष की आयु के बच्चे स्कूलों में नहीं हैं।

भारत में पूर्ण गरीबी ने औपचारिक शिक्षा की खोज को भी रोक दिया है क्योंकि शिक्षा को अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की तुलना में गरीबों में सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं माना जाता है। एमआरपी-आधारित (मिश्रित रिकॉल अवधि) गरीबी का अनुमान है कि 2004-05 में लगभग 22ः गरीबी, जिसका अर्थ प्रति 100 लोगों में से 22 है, अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि बच्चे शिक्षा की जरूरत को पूरा करेंगे।

निरक्षर महिलाओं का बड़ा अनुपात भारत में कम साक्षरता का एक और कारण है। लिंग अंतर के आधार पर असमानता के कारण महिला साक्षरता दर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में 75.8ः पर 54.2ः कम रही। महिला और पुरुष भूमिकाओं की मजबूत रूढ़िवादिता के कारण, लड़कों को अधिक उपयोगी माना जाता है और इसलिए उन्हें शिक्षित किया जाता है। महिलाओं को घर पर कृषि फार्मों में मदद करने के लिए खींचा जाता है क्योंकि वे पुरुषों की जगह ऐसी गतिविधियों में भाग ले रही हैं जिनके लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। कृषि कार्य में संलग्न 2ः से भी कम लड़कियों ने स्कूल में भाग लिया।

हालाँकि अंग्रेजों ने शिक्षा की नई शैली शुरू की जो भारतीय स्थिति के लिए बेहद अनुपयुक्त थी। जो बच्चे आमतौर पर अपने माता-पिता की मदद करने के लिए फसल पकने के मौसम के दौरान छुट्टी लेते थे, उन्हें अनुशासनहीन माना जाता था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई गंदगी के कारण भारत की साक्षरता दर में लगातार गिरावट आई। अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों के लिए निम्नलिखित आँकड़े उपलब्ध हैं। 1881-82 और 1946-47 के बीच, संख्या

अंग्रेजी प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 82,916 से बढ़कर 134,866 हो गई और अंग्रेजी स्कूलों में छात्रों की संख्या 2,061,541 से बढ़कर 10,525,943 हो गई। भारत में अंग्रेजों के अनुसार साक्षरता दर 1881 में 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 1931 में 7.2 प्रतिशत और 1947 में 12.2 प्रतिशत हो गई।

2000-01 में, 60,840 प्री-प्राइमरी और प्री-बेसिक स्कूल थे, और 664,041 प्राइमरी और जूनियर बेसिक स्कूल थे। प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 1950-51 में 19,200,000 से बढ़कर 2001-02 में 109,800,000 हो गया है। 2000-01 में उच्च विद्यालयों की संख्या स्वतंत्रता के समय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से अधिक थी।

1944 में, ब्रिटिश भारत सरकार ने भारत के शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए सार्जेंट योजना नामक एक योजना प्रस्तुत की, जिसका लक्ष्य देश में 40 वर्षों के भीतर, अर्थात् 1984 तक 1000ः साक्षरता का जाना था। हालाँकि 40 वर्ष की समय-सीमा थी उस समय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं द्वारा सार्वभौमिक साक्षरता हासिल करने के लिए बहुत लंबी अवधि के रूप में उपहास किया गया था, भारत ने 2011 की जनगणना तक केवल 74ः के स्तर को पार किया था।

साक्षरता दर 1951 में 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 1961 में 28.30 प्रतिशत, 1971 में 34.45 प्रतिशत, 1981 में 43.57 प्रतिशत, 1991 में 52.21 प्रतिशत, 2001 में 64.84 प्रतिशत और 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई। इसी अवधि में, जनसंख्या 361 मिलियन से बढ़कर 1,210 मिलियन हो गई।

छत्तीसगढ़ राज्य अपने सीमित संसाधनों और धीमी गति से चलने वाली मशीनरी के साथ अपने अधिकतम, भारतीय लोगों की प्रतिभा को विकसित करने में असमर्थ है। बहुत बार राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली अवैयक्तिक शिक्षा, पर्याप्त सामग्री से रहित, जो छात्रों को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी। इस प्रकार की शिक्षा केवल संभावित पेन-पुशर्स पैदा करने में सफल होती है, न कि गुणवत्तापूर्ण छात्रों को। साक्षरता दर की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 64.7 प्रतिशत के साथ देश में 23वां स्थान है, जिसमें से 77.4ः पुरुष सदस्य साक्षर हैं, जबकि 51.9ः महिला साक्षरता दर उद्धृत की गई है। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों की साक्षरता दर नीचे दिया गया है।

कुछ जिलों की उच्चतम और निम्नतम साक्षरता दर

	Highest lit. rate		Lowest lit. rate	
Sn	Name of the District	Literacy rate	Name of the District	Literacy rate
1.	Rajnandgaon	77.55	Dantewada	30.01
2.	Durg	75.84	Bastar	45.48
3.	Dhamtari	75.16	Surgical	50.37
4.	Kanker	73.31	Bilaspur	63.50

Scanned by CamScanner

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-8* November-2021
Anthology : The Research

इस परिदृश्य में जहां अधिकांश सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है, प्रख्यात शिक्षाविदों, परोपकारी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा कई निजी शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं और गैर-अल्पसंख्यकों में से एक है

अध्ययन का उद्देश्य

जो छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, साथ ही अन्य उद्देश्य, जैसे,

1. रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त करना
2. सर्वोत्तम और 100: परिणाम प्राप्त करने के लिए
3. अनुशासित स्कूल और कॉलेज रखना
4. समुदाय और राष्ट्र के लिए भविष्य के ईमानदार नेता तैयार करना
5. छात्रों का सर्वांगीण संतुलित विकास करना
6. छात्रों के मजबूत चरित्र का निर्माण करना।

सरकारी अनुमान के अनुसार, भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के 200 मिलियन बच्चों में से लगभग 59 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बाकी में से, जो वर्तमान में स्कूल में हैं, स्कूल जाने वाले प्रत्येक 10 में से चार बच्चे अपनी प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देंगे। इसके अलावा, बच्चों की सीखने की उपलब्धि के विभिन्न अध्ययनों से संकेत मिलता है कि स्थिति वास्तव में गंभीर है। हाल ही में देश के 28 शहरों और आठ ग्रामीण जिलों में किए गए समुदाय आधारित सर्वेक्षणों में पाया गया कि महाराष्ट्र जैसे शैक्षिक रूप से उन्नत राज्य में 6 से 14 आयु वर्ग के 30 प्रतिशत से अधिक स्कूली बच्चे सरल नहीं पढ़ सकते हैं। धाराप्रवाह पाठ या बुनियादी अंकगणितीय योग नही कर सकते।

प्रदान की जाने वाली शिक्षा का उद्देश्य न केवल प्राप्त ज्ञान की मात्रा में परिवर्तन लाना होना चाहिए, बल्कि ऐसा करने की क्षमता, सोचने और आदतों, कौशल और दृष्टिकोण को प्राप्त करना भी होना चाहिए जो एक ऐसे व्यक्ति की विशेषता है जो सामाजिक रूप से स्वीकृत और समायोजित है।

शिक्षा एक अंत का साधन है, जिसमें हर कोई शिक्षा के सशक्त प्रभाव और लोगों को समाज, सरकार, मौजूदा लैंगिक और सांस्कृतिक स्टीरियो-प्रकारों के प्रति एक महत्वपूर्ण प्रश्नात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम बनाने में विश्वास करता है।

आज, यह ध्यान दिया गया है कि भारत के सभी राज्यों और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पुरुष लोक की तुलना में महिला लोक की साक्षरता दर कम है। कारण बहुत स्पष्ट हैं।

1. स्वभाव से स्त्री लोक को नर लोक की तुलना में दूसरी स्थिति के रूप में माना जाता है।
2. समाज/समुदाय में पुरुष लोक की तुलना में महिला लोक को दूसरे स्थान पर धकेलने की पारंपरिक आदत है। बालिका के जन्म से लेकर मृत्युशय्या तक, पालने से लेकर कब्र तक, यह देखा गया है कि लड़के की तुलना में लड़की को वरीयता या प्राथमिकता नहीं दी जाती है।
3. एक बालिका को कम महत्वपुर्ण माना जाता है क्योंकि उसे शादी के बाद परिवार से दूसरे परिवार में जाना पड़ता है।
4. कुछ समुदायों में, पर्दाप्रथा अभी भी कायम है, जो महिलाओं को कोकून में रखती है।
5. अधिकांश समुदायों में, ग्रामीण लोग लड़कों को प्राथमिकता देते हैं और वे बालिकाओं की परवाह नहीं करते हैं और लड़कियों को स्कूलों में नहीं भेजते हैं।
6. लोगों की नकारात्मक मानसिकता वास्तव में महिलाओं के शिक्षा स्तर को प्रभावित कर रही है।

निष्कर्ष

संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि जब तक समाज बालिकाओं की शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूक नहीं होगा और शिक्षा के संबंध में सरकार द्वारा योजनाओं और परियोजनाओं को सही ढंग से और ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है, तब तक महिला शिक्षा की स्थिति है स्थिर रहेगीवह और गतिशील नहीं होगी। सरकार निश्चित रूप से प्रत्येक बालिका को नामांकन सूची में लाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार, राजनीति, उदासीन नेताओं, शिक्षा के व्यावसायीकरण, शिक्षा के स्तर और विशेष रूप से महिला शिक्षा के निम्न स्तर के कारण नहीं है। अगर मैं कहूं कि भ्रष्टाचार और लालच समाज में सभी बुराइयों की जड़ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आशा करते हैं, एक दिन महिला लोक सभी का नेतृत्व करेगी

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *http://www.nlm.nic.in/women.html*
2. *http://vibranthistory.blogspot.com/2007/07/female-education-in-india.html*
3. *https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/in.html*
4. *http://www.indianembassy.org/Policy/Children_Women/rights_privileges.html*
5. *http://www.indianembassy.org/Policy/Children_Women/policies_women.html*
6. *Main article: Literacy in India*

Scanned by CamScanner